जे. वी. गुप्ता, के समक्ष जे.

तेजिंदर ,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी।

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 3234

26 जुलाई 1989.

एयर क्राफ्ट अधिनियम (1934 का XXII) - धारा 6 - एयर क्राफ्ट नियम, 1937 - नियम 39-ए (2) - सार्वजनिक हित में याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द - सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया - ऐसे आदेश की वैधता।

माना गया कि चूंकि मामला काफी संवेदनशील था, क्योंकि यह कंपनी की सुरक्षा से जुड़ा था। एक बार जब याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया और विमान का उपयोग करने की अनुमति दी गई, तो शरारत होगी और लाइसेंस रद्द करने का मूल उद्देश्य विफल हो गया होगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि याचिकाकर्ता अपना लाइसेंस रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर पाने का हकदार था। इस न्यायालय में प्रस्तुत रिकॉर्ड फ़ाइल में निहित याचिकाकर्ता के खिलाफ गुप्त रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। (पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय परमादेश या सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट या ऐसे अन्य रिट, आदेश पर निर्देश जारी करने की कृपा करें जैसा कि यह माननीय उच्च न्यायालय उचित और उचित समझे मामले की परिस्थिति में;

(i) उत्तरदाताओं को मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना होगा।

(ii) नागरिक उड्डयन महानिदेशक संख्या 1-999/83-एल(एल) दिनांक 3 दिसंबर 1986 (अनुलग्नक पी. 1) के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसमें याचिकाकर्ता को एयर क्राफ्टरूल्स1937 के तहत अनुमत किसी भी लाइसेंस को रखने से रोक दिया गया था। .

(iii) याचिकाकर्ताआर का निजी पायलट लाइसेंस उसे लौटाने के लिए।

(iv) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे उसे बिना किसी रोक-टोक के उड़ान प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति दें और जुलाई, 1987 से शुरू होने वाली विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं में शामिल हों, जिन्हें याचिकाकर्ता के लिए मई, 1988 से पहले उचित चरणों में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। .

(v) ऐसे अन्य निर्देश या आदेश पारित करना जो माननीय उच्च न्यायालय उचित और उचित समझे; और

(iv)) याचिकाकर्ता को लागत पुरस्कार देना।

याचिकाकर्ता के लिए जी एस ग्रेवाल वरिष्ठ अधिवक्ता और एस एस बाजवा अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से एच. एस. बराड़, वकील।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

1)) याचिकाकर्ता को अपना निजी पायलट लाइसेंस, संख्या 3651, 22 जनवरी 1986 को महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, (इसके बाद डीजीसीए कहा जाएगा) से मिला और साथ ही वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उक्त लाइसेंस डीजीसीए द्वारा दिसंबर, 1986 में वापस ले लिया गया था - अनुबंध पीएल के अनुसार। इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में चुनौती दी है। उक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को विमान नियम, 1937 (इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) के नियम 39-ए के उप-नियम (2) के तहत लाइसेंस रखने से रोक दिया गया है। यह प्रदान करता है : -

"केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नियम 38 में उल्लिखित किसी भी लाइसेंस को रखने से स्थायी या अस्थायी रूप से रोक सकती है यदि उसकी राय में सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।"

2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि विमान अधिनियम, 1934 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 6, केंद्र सरकार को आपातकालीन स्थिति में आदेश देने का अधिकार देती है। विद्वान वकील के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की राय है कि सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में उसमें उल्लिखित सभी या किसी भी आदेश को जारी करना समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश दे सकती है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार धारा 6'(1) (ए) के तहत केवल सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, जबकि उपरोक्त नियम के तहत, लाइसेंस सार्वजनिक हित में रद्द किया जा सकता है, जो कि विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम के दायरे से बाहर था। मुझे इस विवाद में कोई दम नहीं दिखता|

(3) अधिनियम की धारा केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति नहीं देती है। यह केवल की शक्तियों का प्रावधान करता है

केंद्र सरकार आपातकाल में आदेश दे. नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है: -

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी विमान या विमान के वर्ग के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात या निर्यात को विनियमित करने और विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं, -

(ए) से (एफ)

(छ) विमान के संचालन, निर्माण, मरम्मत या रखरखाव में नियोजित व्यक्तियों को लाइसेंस देना;

(एच) से (आरआर)

परिणामस्वरूप, नियम बनाए गए हैं, जिन्हें विमान नियम, 1937 के नाम से जाना जाता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि विमान अधिनियम 1934, (1934 का XXII) की धारा 5 और 7 और धारा 8 की उप-धारा (2) और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1855 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (XXII of 1885), केंद्र सरकार उक्त नियम बनाकर प्रसन्न है।

(4) इस स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियमों के नियम 39-ए के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद संतुष्ट है, कोई भी व्यक्ति आदतन अपराधी है या आदतन शराब पीने में असंयमी है, या नशीले पदार्थों, नशीली दवाओं आदि का आदी है, या किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने के लिए विमान का उपयोग कर रहा है, उसका उपयोग कर चुका है, या करने वाला है। या इन नियमों का उल्लंघन करते हुए, या किसी विमान के चालक दल के सदस्य के रूप में अपने पिछले आचरण से, यह दर्शाया गया है कि वह अपने रोजगार से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन में गैर-जिम्मेदार है या विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावना है। या उसमें ले जाए गए किसी भी व्यक्ति या वस्तु, या अन्य विमान या व्यक्तियों या जमीन पर मौजूद चीजों के लिए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, लिखित रूप में, उस व्यक्ति को लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश दे सकता है। विद्वान वकील के अनुसार नियम 39-ए का उप-नियम (2) जो केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी लाइसेंस को रखने से वंचित करने का अधिकार देता है, उसे यह भी आवश्यक होना चाहिए कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। . इस प्रकार, अर्जित वकील ने तर्क दिया, चूंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए लागू आदेश रद्द किया जाने योग्य है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि न केवल उक्त नियम के अनुसार, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर भी, चूंकि लाइसेंस रद्द करने से याचिकाकर्ता के नागरिक अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिए वह अपना लाइसेंस वापस लेने से पहले एक नोटिस का हकदार था। इसके अभाव में, पारित आदेश मनमाना था और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित हुआ। विवाद के समर्थन में, विद्वान वकील ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1) पर भरोसा किया, विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैराग्राफ 61 पर। उसमें यह देखा गया कि कानून को अब अच्छी तरह से स्थापित माना जाना चाहिए कि एक प्रशासनिक कार्यवाही में भी, जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू माना जाना चाहिए।

(5) भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि लाइसेंस सार्वजनिक हित में रद्द कर दिया गया है। यह एक संवेदनशील मामला था क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा था। चूँकि लाइसेंस विमान उड़ाने के लिए था, एक बार उसे ऐसा करने की अनुमति मिल जाती, तो शरारत हो जाती। इन परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने तर्क दिया, लाइसेंस रद्द करने से पहले कोई नोटिस जारी करने का प्रश्न उचित नहीं था। विवाद के समर्थन में, विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम चरणजीत कौर (2) पर भरोसा किया।

(6) सुनवाई की अंतिम तिथि पर, भारत संघ के विद्वान वकील को इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत फ़ाइल पेश करने का निर्देश दिया गया था, जिसे आज पेश किया गया है।

(7) जहां तक मेनका गांधी के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का संबंध है, निर्णय के पैराग्राफ 61 में यह इस प्रकार देखा गया:

"प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। किसी दिए गए मामले में प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम लागू होना चाहिए, यह काफी हद तक उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, कानून की रूपरेखा जिसके तहत जांच की जाती है और ट्रिब्यूनल या उस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों के निकाय के गठन पर निर्भर होना चाहिए। .

जब भी किसी न्यायालय के समक्ष शिकायत की जाती है कि प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है तो न्यायालय को यह निर्णय लेना होगा कि मामले के तथ्यों पर उचित निर्णय के लिए उस नियम का पालन आवश्यक है या नहीं।

इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उक्त टिप्पणियों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मामला काफी संवेदनशील था, एक बार याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया और विमान का उपयोग करने की अनुमति दी गई, शरारत ऐसा होता और लाइसेंस रद्द करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि याचिकाकर्ता अपना लाइसेंस रद्द करने से पहले सुनवाई के अवसर का हकदार था। इस न्यायालय में प्रस्तुत रिकॉर्ड फ़ाइल में निहित याचिकाकर्ता के खिलाफ गुप्त रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

(8) परिणामस्वरूप, यह रिट4.याचिका5 विफल हो जाती है और मुझे लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh